Role of State in Economic Development

Classical & Neo-classical economists आर्थिक विकास में राज्य के हस्तक्षेप को सीमित माना था लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रीयों ने आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। Keyns ने अपनी पुस्तक "End of Laissez-faire" में यह स्पष्ट किया कि आर्थिक विकास में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। पूंजीवाद में उद्योग के संगठन एवं संचालन का कार्यभार निजी उद्यमी पर ही रहता है किन्तु सरकार तरह तरह के नियमों को बनाकर उद्यमी के अनुचित कार्यों पर नियंत्रण रखती है। उद्यमी का निर्णय अर्थव्यवस्था के विकास को तीव्र करने में सहायक हो रहा है या नहीं, इस सरकार निगरानी रखती है और आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप करती है। Oscar Lange के अनुसार " The public investment would become the strategic lever of economic development of under-developed countries."
आर्थिक विकास में सरकार की भूमिका को दो भागों में बाँटा जाता है।

1. विकासात्मक भूमिका (Developmental Roles)
2. नियामक भूमिका (Regulatory Roles)

Developmental Roles :-

1. आर्थिक एवं सामाजिक संरचना का निर्माण — निजी क्षेत्र में तत्काल लाभ मिलने वाले कार्य किये जाते हैं। आर्थिक संरचना जैसे बिजली, सिन्चाई के साधन, संचार के साधन आदि में तत्काल लाभ नहीं होता है। इसलिए निजी विनियोग इस क्षेत्र में आरंभ नहीं होते हैं। सरकार को स्वयं इन क्षेत्रों में सार्वजनिक विनियोग करना होता है। सामाजिक संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, मनोरंजन आदि के विकास

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

हेतु सरकारी विनियोग ही आवश्यक होता है।

2. कृषि में विकास

कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष भूमिका सरकार की होती है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार कृषि में तकनीकी परिवर्तन हरित क्रान्ति के द्वारा लाती है तथा भूमि सुधार के द्वारा संगठनात्मक परिवर्तन लाती है। 'HYV - Fertiliser - Tractor' तकनीकी को कृषि में प्रयुक्त कर अनाज के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता लाती है।

3. औद्योगिक विकास

सरकार औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिकरण के दर एवं ढांचा में परिवर्तन करती है। भारी एवं आधारभूत उद्योगों की स्थापना करती है। नई-नई औद्योगिक नीति को अपनाती है जिससे आर्थिक विकास को बल मिल सके।

4. गरीबी के दुश्चक्र को तोड़ना

अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख समस्या गरीबी का दुश्चक्र है जो कि मांग पक्ष एवं पूर्ति पक्ष दोनों के संदर्भ में रहता है। इसे निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है-

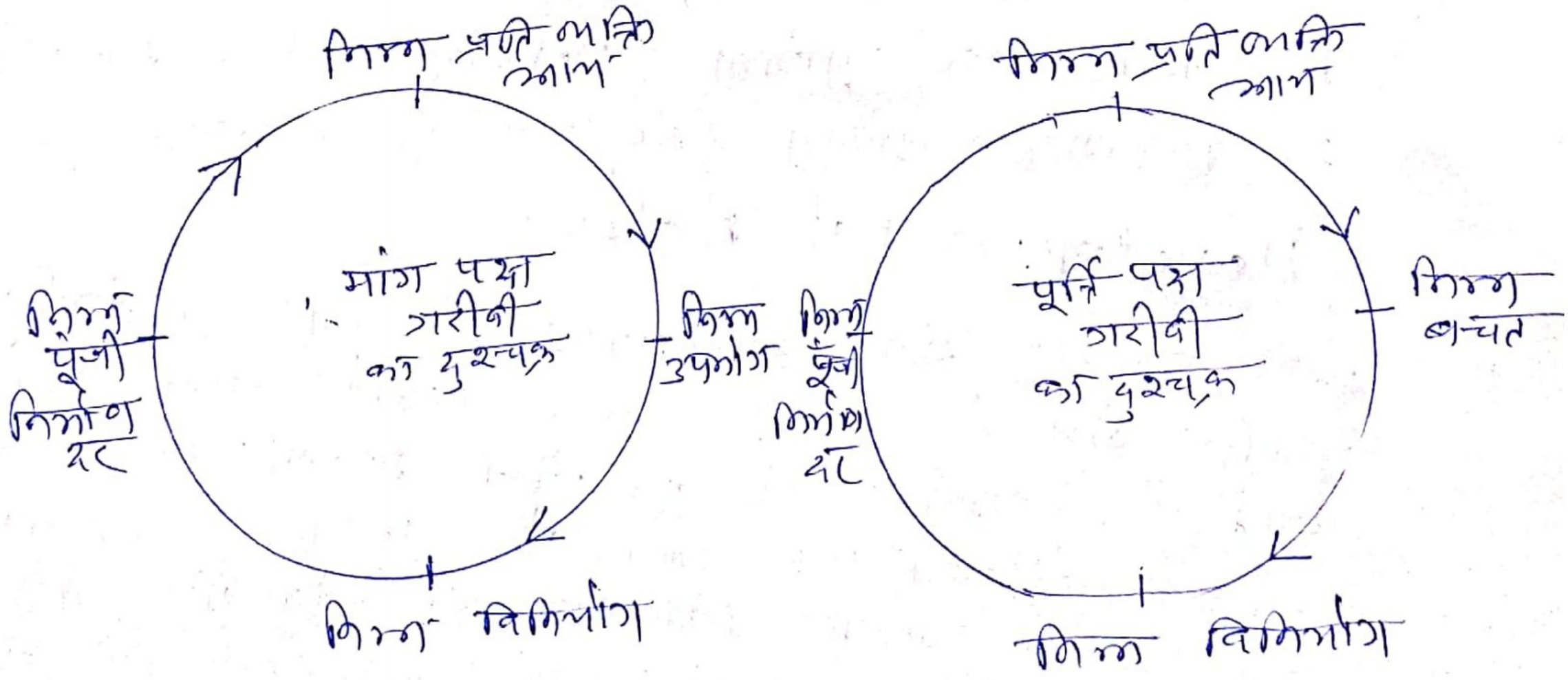

उपरोक्त चित्र में मांग पक्ष तथा पूर्ति पक्ष दोनों तरफ गरीबी का दुश्चक्र चलता है। इसे तोड़ने के लिए

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

राज्य की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। बहुत अधिक मात्रा में सरकार विनियोग करती है ताकि गरीबी का दुश्चक्र तोड़ा जा सके और "Virtuous cycle of economic growth" स्थापित हो। इसे निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है -

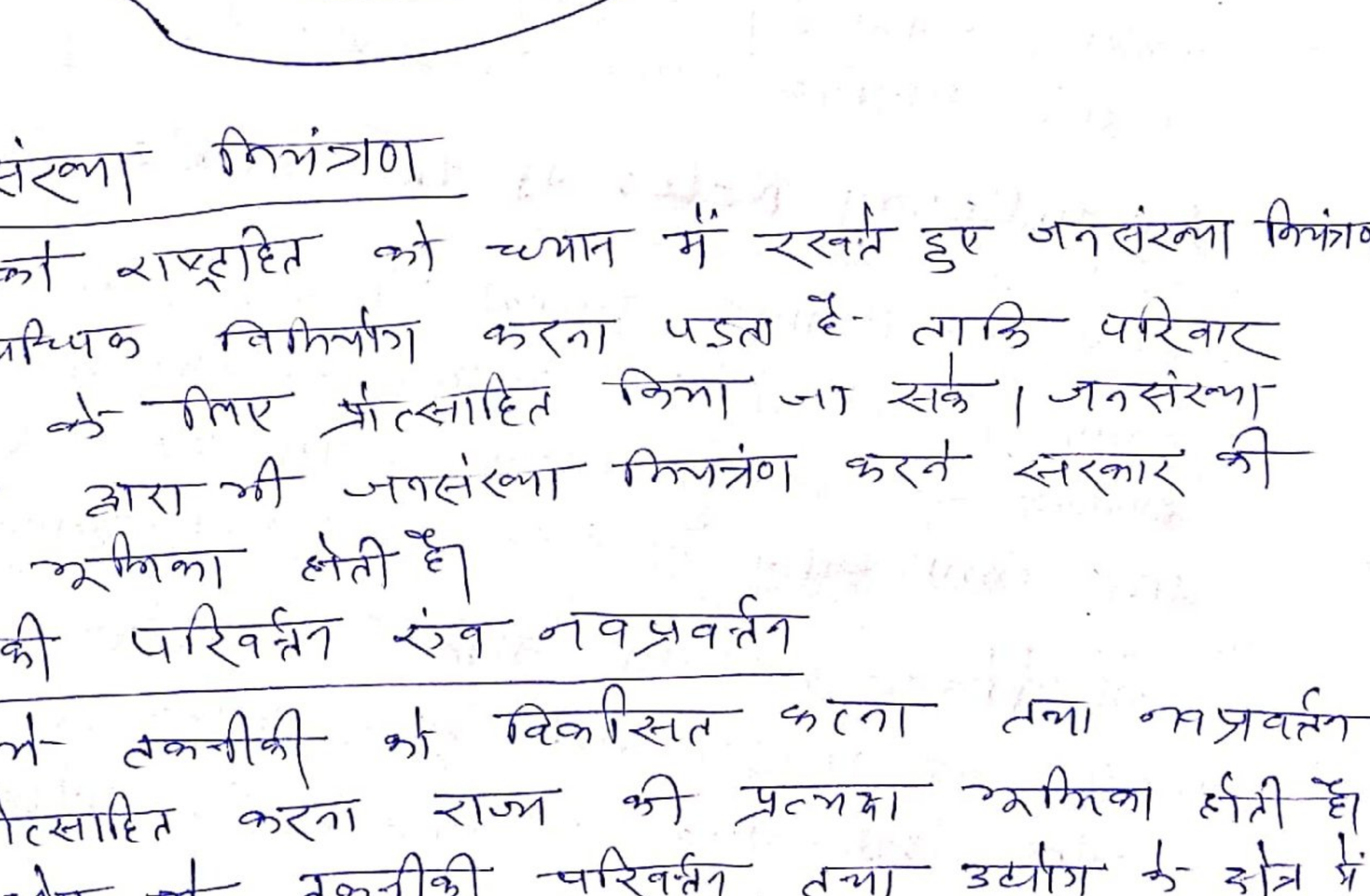

5. जनसंख्या नियंत्रण

सरकार को राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण पर अत्यधिक विनियोग करना पड़ता है ताकि परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। जनसंख्या नीति के द्वारा भी जनसंख्या नियंत्रण करने सरकार की प्रत्यक्ष भूमिका होती है।

6. तकनीकी परिवर्तन एवं नवप्रवर्तन

नये नये तकनीकी को विकसित करना तथा नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना राज्य की प्रत्यक्ष भूमिका होती है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन तथा उद्योग के क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन लाने के लिए राज्य वित्तीय सहायता देती है।

7. प्राकृतिक संसाधनों के अपव्यय पर रोक

प्राकृतिक साधन एवं सम्पदा की सही देखभाल राज्य द्वारा राष्ट्रहित में किया जाता है। भूमि क्षरण को रोकना, खदानों से खनिज निकालने पर नियंत्रण, जंगल काटने पर नियंत्रण आदि कार्यों को राज्य सम्पन्न करती है।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

8. सुरक्षा व्यवस्था

आर्थिक विकास के लिए देश में न केवल आंतरिक शांति होना जरूरी है बल्कि विदेशी आक्रमणों से निपटने के लिए शक्तिशाली सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी होती है। जिसे केवल राज्य ही कर सकती है।

9. पूर्ण रोजगार एवं सामाजिक न्याय

अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दूर करने में तथा पूर्णरोजगार प्राप्त करने में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में रोजगार कार्यक्रम जैसे ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, PMRY तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना राज्य चला रही है। गरीब वर्ग के लोगों को जनवितरण प्रणाली के द्वारा सस्ते मूल्यों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। ये सभी राज्य के प्रत्यक्ष कार्यवाही है जिससे सामाजिक न्याय की प्राप्ति होती है।

Regulatory Roles of the State

राज्य की नियामक भूमिका भी आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहित करती है। निजी क्षेत्रों के उद्यमियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण एवं नियमन समय-समय पर सरकारी नीतियों द्वारा किया जाता है। राज्य की नियामक भूमिका निम्नलिखित है

औद्योगिक लाइसेंस नीति, करारोपण नीति, साख नीति आय एवं मजदूरी नीति, मूल्य नीति, तकनीकी एवं रोजगार नीति, श्रम नीति, आयात-निर्यात नीति, विदेशी मुद्रा नीति, तटकर नीति

इन सभी नीतियों से राज्य बाजार व्यवस्था में हस्तक्षेप करती है ताकि राष्ट्रहित में निजी उद्योगपति कार्य करें तथा आर्थिक संवृद्धि की दर तेज हो।

ⓐ वर्तमान समय में राज्य के नियामक भूमिका के अन्तर्गत Tax Holiday तथा कर की छूट की नीति प्रमुख है।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

(b) न्यूनतम मजदूरी कानून को लागू कर आय के वितरण की विषमता को राज्य दूर करती है।

(c) मुद्रास्फीति के समय महँगी साख नीति तथा अवसाद या मंदी के समय सस्ती साख नीति को सरकार अर्थव्यवस्था में लागू करती है। ब्याज कटौती से भी निवेशकर्ता प्रभावित किये जाते हैं।

इसप्रकार राज्य की विकासात्मक भूमिका को प्रथम चरण का कार्य एवं नियामक भूमिका को द्वितीय चरण के कार्य कहा जाता है जिसे चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं –

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

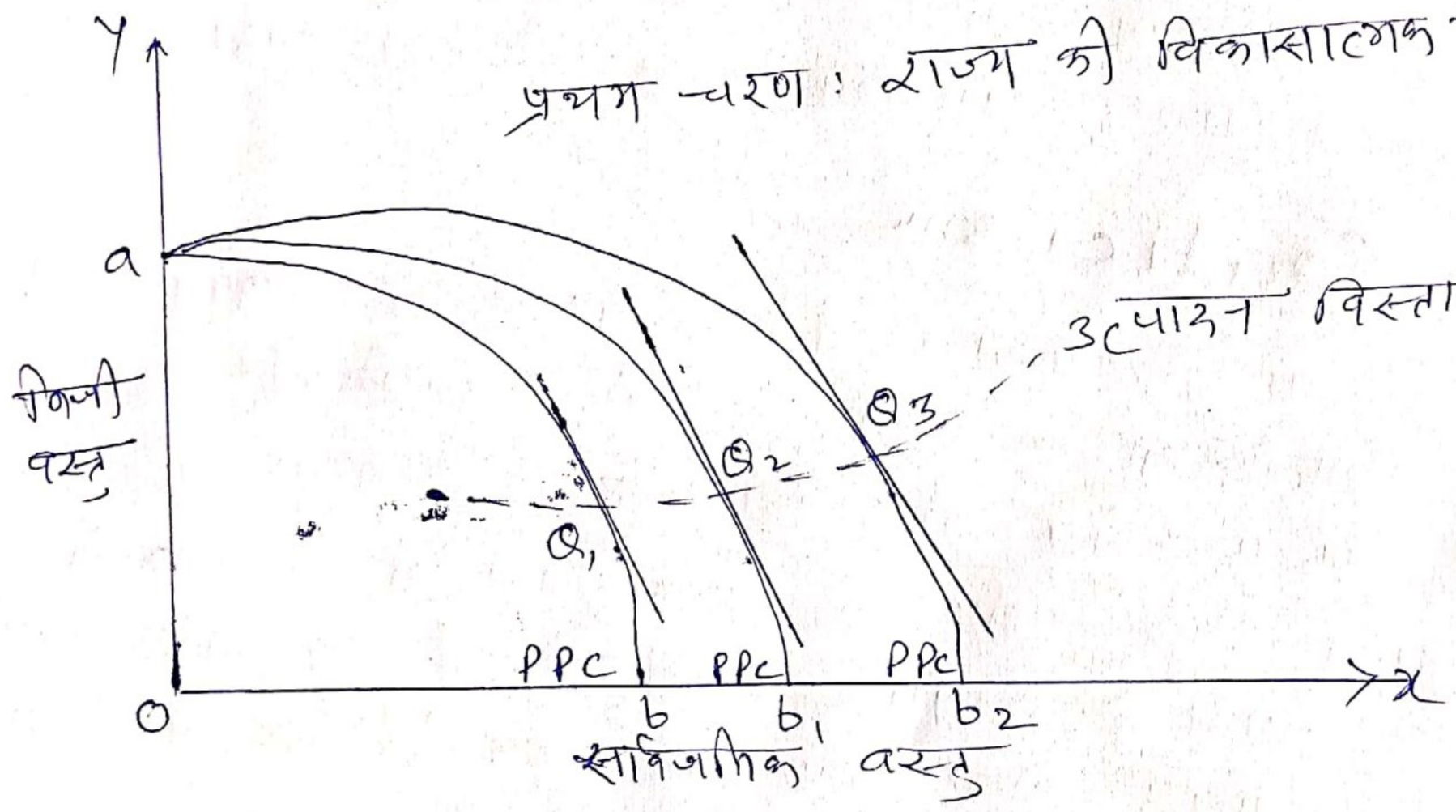

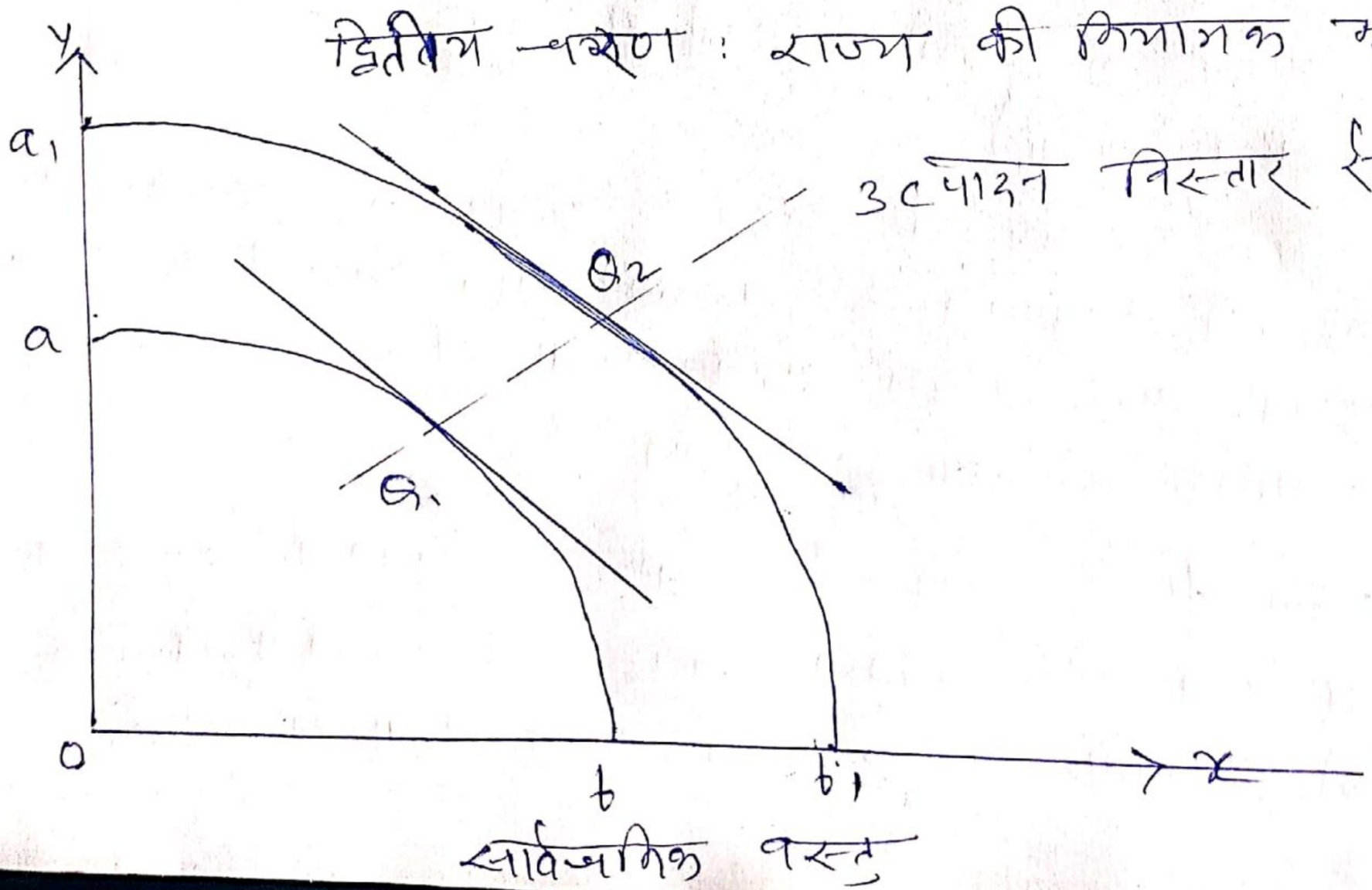

उपयुक्त चित्र में प्रथम चरण में आर्थिक विकास की गति तीव्र करने के लिए सरकार स्वयं विकासात्मक परियोजनाओं पर अत्यधिक व्यय करेगी ताकि आर्थिक संरचना में वृद्धि हो जाय।

द्वितीय चरण में राज्य नियामक भूमिका के माध्यम से किसी क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि कराने में सहायक होगी। इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास तेज होगा।

इस प्रकार आर्थिक विकास में राज्य की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भूमिका होती है। विकासात्मक भूमिका राज्य की प्रत्यक्ष भूमिका होती है जबकि नियामक भूमिका राज्य की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है

Criticism

आर्थिक विकास में राज्य के हस्तक्षेप की कड़ी आलोचना की गई है जो निम्नलिखित है —

1. बाजार तंत्र में विसंगतियाँ उत्पन्न करना

राज्य के हस्तक्षेप से बाजार तंत्र में विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती है क्योंकि किसी उद्यमी सरकारी हस्तक्षेप से आहत होकर विनियोग घटा देते है। इससे राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आती है।

2. लालफीताशाही

राज्य हस्तक्षेप से सरकारी अफसरवाद स्थापित हो जाता है सरकारी अफसरों के ~~व्यवहार~~ लालफीताशाही के कारण किसी उद्यमी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

3. आर्थिक स्वतंत्रता का हनन

राज्य के हस्तक्षेप से आर्थिक स्वतंत्रता का हनन होता है उपभोक्ता की स्वतंत्रता, मजदूर की स्वतंत्रता तथा उत्पादक की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्पत्ति के साधनों

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

की गतिशीलता में बाधा उत्पन्न होता है।

4. स्वचालित मूल्य तंत्र की समाप्ती

राज्य के हस्ताक्षेप से बाजार तंत्र के द्वारा मूल्य परिवर्तन का संकेत एवं निर्देशन निजी उद्यमी को नहीं मिल पाता है। उत्पादन का निर्णय सरकारी निर्णय बन जाता है जो कि बेलोचता के दुर्गुण से ग्रसित है।

5. प्रेरणा का अभाव

राज्य के हस्ताक्षेप करने से ~~[illegible]~~ आर्थिक व्यवस्था में लाभ प्रवृत्ति रूपी प्रेरणा का अभाव हो जाता है। सभी आर्थिक क्रियाएँ सरकारी आज्ञा का इंतजार करती है।

6. गुलामी का मार्ग "Road to Serfdom"

Prof Hayek के अनुसार राज्य की सारी क्रियाएँ नियोजन के माध्यम होती है। नियोजन या योजनाकरण अर्थव्यवस्था को गुलामी के मार्ग पर ले जाती है। योजना आयोग ही सभी निर्णय लेगा कि देश में कितना उत्पादन होगा और कैसे वितरण होगा। इसलिए योजना गुलामी का मार्ग है जिसे राज्य हस्ताक्षेप से लागू किया जाता है।

7. ~~निजी~~ विनियोग में बाधा

राष्ट्रीयकरण के भय से देश के पूंजीपति अपनी पूंजी को देश में लगाना पसन्द नहीं करते। इसके अतिरिक्त विदेशी पूंजी भी हतोत्साहित होती है। फलस्वरूप औद्योगीकरण की गति धीमी रहती है।

—x—

Dr Sandhya Rani
Maharaja College